इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 05 दिसम्बर 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं-- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां--2
बैंकिंग जगत की घटनाएं--2
प्रवृत्ति एवं प्रगति---3
विनियामकों के कथन ---3
सहकारी बैंक--4
सूक्ष्मवित्त---4
बीमा---5
पूंजी बाज़ार---5
पण्य (जिंस) बाज़ार---5
अंतरराष्ट्रीय समाचार---5
अर्थव्यवस्था---6
नयी नियुक्तियां--6
उत्पाद एवं गंठजोड---6
संस्थान समाचार---7
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक--7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं -- 7
शब्दावली ---8
बाज़ार की खबरें---8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की अंतरण सीमा 2 लाख रुपये तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) की प्रारंभिक लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 2 लाख रुपये कर दी है, इस प्रकार बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपये के लागत-रहित अंतरण की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) के लिए एक नयी मूल्य पट्टी भी लागू की है। संशोधित दरों के अनुसार बैंक 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के लेनदेनों के लिए 25 रुपये तथा 5 लाख रुपये से अधिक वाले लेनदेनों के लिए 50 रुपये का सेवा प्रभार वसूल कर सकते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने ग्राहकों को पूर्व-प्रदत्त कार्ड जारी करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कार्ड प्रभाग को ऐसे पूर्व-प्रदत्त कार्ड जारी करने की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसमें पॉलिसी से होने वाले लाभ जमा होंगे। बैंक निगम द्वारा उसके ग्राहकों को किए जाने वाले या तो एकबारगी या फिर आवधिक भुगतानों को जमा करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को पूर्व-प्रदत्त लिखत जारी कर सकते हैं।

एटीएमों की स्थापना करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अग्रणी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब देश में एटीएमों के प्रसार को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में ऑफसाइट एटीएमों की संख्या में 70% की बढ़ोत्तरी हुई, जिससे वह अब बढ़कर

16,883 (9,898) हो गई है। स्टेट बैंक समूह ने अपने ऑफसाइट एटीएमों की संख्या दोगुने से भी अधिक बढ़ा कर पिछले वित्तीय वर्ष के 4, 193 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2009-10 में 9, 836 कर दी है। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उनके ऑफसाइट एटीएमों की संख्या लगभग 24% बढ़ा कर पिछले वित्तीय वर्ष के 5, 705 के मुकाबले 7, 047 तक पहुंचा दी है।

सरकार बैंकरों के समूह का गठन करेगी

केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक सहायता संघ का गठन करने वाली है। उक्त सहायता संघ राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत स्थापित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के लिए अल्प लागत वाले निधीयन उपलब्ध कराने के लिए (विशेष लिखतों जैसे) अर्थोपायों पर चिंतन करेगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

वित्तीय समूह क्रमवीक्षण के दायरे में

विविधीकृत व्यावसायिक हितों वाले वित्तीय समूहों की जोखिम प्रोफाइल को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहायक कम्पनियों में उनकी अनाश्रयता इन कम्पनियों की प्रदत्त इक्विटी (इसके पूर्व 30% की तुलना में) के 20% से अधिक होने पर उनसे और अधिक पूंजी बचा रखने के लिए कहा है।

आस्ति की कीमतों, विनिमय दरों पर निगरानी रखी जाएगी

इस भय की पृष्ठभूमि में कि उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) में भारी पोर्टफोलियो अंतर्वाह मुद्रास्फीति और बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, आस्ति की कीमतों और विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गहनतापूर्व निगरानी रखी जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की अगुवाई में हुई पूंजी अंतर्वाहों में पर्याप्त वृद्धि ने स्टॉक की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है तथा अमरीकी डालर के समक्ष घरेलू मुद्रा को सुदृढ़ बना दिया है। इसके अलावा, बढ़ते ब्याज दर अंतरों के साथ वैश्विक ऋण बाज़ार की सुधरी हुई स्थितियों ने कारपोरेट क्षेत्र की बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) तक अपेक्षाकृत अधिक पहुंच को सुगम बना दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा है। एटीएमों और नेट-बैंकिंग सुविधाओं के उपलब्ध होने के बावजूद टेलर काउंटरों के समक्ष लम्बी कतारों पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात के लिए उत्सुक है कि बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाएं और इसके लिए अपने ग्राहकों को लेनदेन के लिए उपलब्ध तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS), राष्ट्रीय इलेट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (NEFT) और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS) जैसे विविध प्रकार के विकल्पों के बारे में शिक्षित करें।

न्यूनतम जमा-शेष के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अधिक पारदर्शी बनने और यथोचित दंडात्मक प्रभार वसूल करने के लिए कहा है। किसी बचत खाते में न्यूनतम जमा-शेष में मामूली सी गिरावट होने पर भी बैंकों द्वारा भारी जुरमाना लगाए जाने के बारे में ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों में वृद्धि हुई है। ग्राहकों के मामूली आधार पर दंडित किए जाने की घटनाएं भी विनियामक के ध्यान में आने से नहीं बची हैं। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके बावजूद भी इन प्रभारों को निर्धारित करने का निर्णय अलग-अलग बैंकों पर छोड़ देने की अपनी पूर्ववर्ती नीति पर कायम रहेगा।

बैंकों के लिए गैर-वित्तीय कम्पनियों में निवेश करने के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा : भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-वित्तीय कम्पनियों में बैंकों के निवेश अब भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुवीक्षण के तहत होंगे, क्योंकि उन्हें गैर-वित्तीय कम्पनियों को ऋण देने अथवा उनमें निवेश करने के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। वित्तीय सेवाओं के अलावा किसी अन्य कारबार में संलग्न कम्पनियों में बैंकों के निवेशों को विनियमित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने विवेकसंमत सीमाएं प्रस्तावित की हैं। इसके अलावा, बैंकों के लिए इस प्रकार की कम्पनियों में उनके निवेशों की पुनरीक्षा किए जाने तथा निर्धारित की जाने वाली रूपरेखा के अनुसार दिशानिर्देशों का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता होगी।

निर्यात आदेशों का समाधान ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने कठोर रुख अपनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात से सम्बन्धित प्राप्तियों का समाधान ऑनलाइन भुगतान के प्रवेश द्वार

(OPG) के माध्यम से किए जाने के लिए कठोर दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के बैंकों को ऑनलाइन भुगतान के प्रवेश द्वार सेवा-प्रदाताओं (OPGSP) के साथ प्रेषण व्यवस्था करते हुए निर्यात से सम्बन्धित प्राप्तियों के प्रत्यावर्तन का संचालन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से एकबारगी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा प्रत्येक ऑनलाइन भुगतान के प्रवेश द्वार सेवा-प्रदाता (OPGSP) के साथ की गई व्यवस्था के ब्योरों की रिपोर्ट देनी होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने से सम्बन्धित नियमों में ढील दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को 50, 000 से कम की जनसंख्या वाले शहरों में उसकी अनुमति के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कम से कम 9% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) तथा 5% से कम निवल अनर्जक आस्तियों जैसे कुछेक विनियामक प्रावधानों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, उसे पिछले वित्तीय वर्ष में निवल लाभ अर्जित किया हुआ होना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए नयी खिड़की खोली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाज़ारों में विघटन को रोकने तथा प्रणाली में ऋण प्रवाह को बनाए रखने के लिए चलनिधि की स्थिति को सुगम बनाने वाले उपायों को पुन: लागू कर दिया है, क्योंकि बढ़ते सरकारी नकदी शेषों के परिणामस्वरूप नकदी की कमी हो जाती है। दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) 16वीं दिसम्बर तक परिचालन में रहेगी और बैंकों को 25% के सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) में एक निश्चित प्रतिशत तक की कमी के लिए जुरमाने से छूट प्राप्त होगी। इससे कारपोरेट बॉण्डों पर उधार लेना और भी अधिक आकर्षक हो गया है। इसके अतिरिक्त चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के रिपोर्टकर्ता शुक्रवार के दिन की उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 2% तक की अतिरिक्त चलनिधि सहायता तात्कालिक प्रभाव से 28वीं जनवरी, 2011 तक उपलब्ध होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े कृषि को ऋण प्रवाह में गिरावट दर्शाते हैं

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उद्योग, सेवाओं और वैयक्तिक ऋण खण्ड को ऋण प्रवाह में तेजी आई है, हालांकि, इसी अवधि में कृषि को ऋण प्रवाह में और गिरावट परिलक्षित हुई है। इसके अलावा, यद्यपि उद्योग को ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है, तथापि वह अभी तक व्यापक आधार नहीं प्राप्त कर सका है। ऋण वृद्धि मुख्यत: आधारभूत सुविधा, लोहा एवं इस्पात, रसायन एवं रासायनिक उत्पादों, अन्य धातुओं एवं धातु उत्पादों एवं इंजीनियरिंग उद्योगों को ऋण प्रवाह द्वारा प्रेरित रही है।

येस बैंक को वेल्स फार्गो से 25 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त

येस बैंक ने अपने लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) ग्राहकों का वित्तीयन करने हेतु अपने लिए अमेरिका स्थित वेल्स फार्गो बैंक से 25 मिलियन डालर का सावधि ऋण प्राप्त किया है। उक्त ऋण संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी एजेन्सी, ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन, जो अमरीकी व्यवसायों की विदेशों में निवेश करने में सहायता करता है, द्वारा गारंटीकृत होगा। भारतीय ढांचे में यह अपने किस्म की पहली व्यवस्था है, जिसमें ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन वेल्स फार्गो को ऋण की आंशिक गारंटी प्रदान कर रहा है।

ऐक्सिस बैंक ने 2,067 करोड़ रुपये के सौदे में एनाम सिक्योरिटी खरीदी

ऐक्सिस बैंक ने 2,067 करोड़ रुपये के मूल्य वाले समस्त स्टॉक सौदे में एनाम का निवेश बैंकिंग और इक्विटी पूंजी बाज़ार कारोबार अधिगृहीत कर लिया है। इसके बाद एनाम श्री मनीष चोकानी (एनाम के निदेशक) की अध्यक्षता वाली ऐक्सिस बैंक की एक सहायक कम्पनी हो जाएगी। एनाम सिक्योरिटीज अपनी निवेश बैंकिंग, संस्थागत एवं खुदरा इक्विटियों तथा सम्बन्धित व्यवसायों यथा-गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी एवं वित्तीय उत्पादों के वितरण को ऐक्सिस बैंक की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी में विलयित कर देगी। बैंक भी अपनी निवेश बैंकिंग इकाई को उक्त सहायक कम्पनी में विलयित कर देगा।

प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट : एक आशुचित्र

बैंकिंग कार्य-निष्पादन

- वाणिज्यिक बैंकों के सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां वित्तीय वर्ष 09 के 2.25% से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 10 में 2.39% हो गईं।

- लाभप्रदता में गिरावट आई, क्योंकि अस्तियों पर प्रतिलाभ (ROA) पिछले वर्ष के दौरान 1.13% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 10 में 1.05% रहा।

- लागत और उसके साथ ही निधियों पर प्रतिलाभ में वर्ष 2009-10 में गिरावट दर्ज हुई। विशेष रूप से, अग्रिमों पर प्रतिलाभ में आई गिरावट, खास तौर पर विदेशी और नये निजी बैंकों के मामले में सर्वाधिक आश्चर्यजनक रही, जो 2008-09 के 10.50% से घट कर वर्ष 2009-10 में 9.29% रह गया।

- कीमत-लागत अंतर अर्थात् प्रतिलाभ और निधि की लागत के बीच अंतर - में वर्ष 2009-10 में 0.10 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट दर्ज हुई। बैंक समूह के स्तर पर, कीमत-लागत अंतर में गिरावट विदेशी बैंकों के मामले में पुन: आश्चर्यजनक रही।

- बैंकिंग क्षेत्र का निवल लाभ 8.3% बढ़ कर 57, 109 करोड़ रुपये हो गया, जबकि परिचालन लाभ 10% बढ़ कर 1, 22, 000 करोड़ रुपये हो गया।

- कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों का अंश वर्ष 2009 के 8.5% से घट कर वर्ष 2010 में 7.2% रह गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अंश 71.9% से बढ़ कर वर्ष 2010 में 73.7% हो गया। पुराने निजी बैंकों ने अपने अंश में मामूली बढ़ोत्तरी की, जो पिछले वर्ष के 4.4% से बढ़ कर 4.5% हो गया, जबकि नये निजी बैंकों का अंश थोड़ा सा घट कर 15.2% के स्थान पर 14.6% हो गया।

- चालू और बचत बैंक (कासा) जमाराशियों का प्रतिशत 2008-09 और 2009-10 की अवधि में 33.2% से बढ़ कर 34% हो गया। वर्ष 2009-10 में जमाराशियों में हुई कुल वृद्धि में अकेले बचत जमाराशियों ने ही लगभग 34% का अंशदान किया।

पहली तिमाही में किसानों को 90, 000 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित

बैंकों ने इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल- जून तिमाही में किसानों को लगभग 89, 687 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 3, 75, 000 करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ने कृषि ऋण प्रवाह बढ़ाने और कृषि ऋणों पर ब्याज दर घटाने के लिए कतिपय उपाय किए हैं। बैंक कृषि ऋण 7% की दर पर प्रदान करते हैं। हालांकि ऐसे किसानों, जो समय पर भुगतान कर देते हैं, को वर्तमान वित्तीय वर्ष से फसल ऋण 5% पर प्राप्त हो रहे हैं।

तुरंत चल भुगतान सेवा का शुभारंभ

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक ऐसी तुरंत अंतरबैंक चल भुगतान सेवा (IMPS) का शुभारंभ कर रहा है, जो सात बैंकों के खुदरा ग्राहकों को 24 X 7 निधि अंतरण सुविधा का उपयोग करने में समर्थ बनाएगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया (BoI), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐक्सिस बैंक और येस बैंक अंतरबैंक चल भुगतान सेवा (IMPS) का उपयोग करने वाले बैंकों के पहले समूह में शामिल हैं।

विनियामकों के कथन

12 नवम्बर, 2010 को इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, मुंबई में "ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिताएं एवं मानक" पर पाठ्यक्रम की शुरूआत के अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती द्वारा दिए गए भाषण से उद्धरण

"हम केवल इस बात की वकालत करते हैं कि ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत सस्ती सेवाएं प्राप्त करना चाहेगा। हालांकि हम कम से कम जो दे सकते हैं वह है निष्पक्षता, गति और सुपुर्दगी। और यह पूर्ण रूप से बैंक के हित में है।

वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक रूप से ग्राहकों के साथ औचित्यपूर्ण व्यवहार करने से सम्बन्धित निम्नलिखित आठ सिद्धांतों को अपनाते हुए ग्राहक परिवादों में कमी लाने का संकल्प करना चाहिए :

1. न्यूनतम शिष्टता और व्यवहारपरक मानक
2. पारदर्शिता
3. गैर-भेदभावपरक नीति
4. वादा (वचन) निभाएं
5. अतिशय जुरमाने के बिना उत्पादों के अविरत बदलान की अनुमति दें
6. एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर ग्राहक परिवाद निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करें
7. 'बेचने' की उपयुक्तता और
8. अनुचित ग्राहक मांगों के विरुद्ध दृढ़ एवं विनम्र दृष्टिकोण

अतएव, समस्या की पहचान कर लिए जाने के बाद क्या किया जाना आवश्यक होता है? यह न तो हार्डवेयर होता है और न ही साफ्टवेयर, अपितु वह ह्यूमनवेयर है, जो ग्राहक सेवा में सुधार ला सकता है। इसलिए अच्छे अभिशासन के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और उसका विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इसलिए

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का यह पाठ्यक्रम प्रासंगिक है। हालांकि, ग्राहक सेवा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत अपने आप में इसका समापन हरगिज़ नही होना चाहिए। इसे अन्य अभिलाषी बैंक कार्मिकों द्वारा आज़माए जाने और इस मान्यता को प्राप्त किए जाने एवं अपने कार्यस्थल पर इस पर अमल किए जाने के उद्देश्य से सकारात्मक प्रति-सूचना देने हेतु कार्य-निष्पादन को मान्यता देने / पुरस्कृत करने जैसे उपायों के माध्यम से उपयुक्त रूप से प्रोत्साहन देते हुए व्यक्तिगत स्तर से संस्थागत स्तर पर आगे ले जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रणब मुखर्जी ने बैंकों से आस्ति की गुणवत्ता सुधारने हेतु कहा

वर्ष 2009-10 में देश के बैंकों के लाभों में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने उनसे आगामी वर्षों में भारत की 9% वृद्धि में सहायता करने में समर्थ होने के लिए आस्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि "बढ़ते प्रतिलाभों और जोखिमों को संतुलित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह आस्ति की गुणवत्ता और विवेकसंगत प्रावधानीकरण पर यथोचित ध्यान देते हुए अर्थव्यवस्था में वृद्धि की इस गति में सहायता प्रदान करे।"

आर्थिक सहायता पर आधारित उधारदायी मॉडेल बनाए रखने लायक नहीं होता : डॉ. सुबीर गोकर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री सुबीर गोकर्ण के अनुसार आर्थिक सहायता पर आधारित उधारदायी मॉडेल बैंकों के लिए बनाए रखने लायक नहीं है तथा यह वित्तीय समावेशन में सहायक नहीं होगा। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि उधार देना ऋणदाताओं को भी व्यवहार्य लगे। ऋणदाता के लिए ऐसी लागत पर उधार देना आवश्यक होता है जो उसे व्यवहार्य बनाने के लिए होने वाले प्रतिलाभ से कम हो। वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य ऋण सुपुर्दगी प्रणाली वित्तीय समावेशन में सहायता नहीं कर सकती। डॉ. गोकर्ण का यह भी कहना है कि "अन्य वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जाने और वित्तीय बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। समावेशन की प्राप्ति से ग्राहकों के पूर्ण रूप से नये समुच्चय की प्राप्ति होगी और वह केवल जमा खातों का ही सृजन नहीं करेगी।"

ऋण संवितरण व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, डॉ. डी. सुब्बाराव का कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने यह मत व्यक्त किया है कि ऋण संवितरण की व्यवस्था में विशेषत: उसके विरुद्ध बढ़ते परिवादों और शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही लाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। वित्त तक पहुंच केवल चंद लोगों का विशेषाधिकार नहीं है; भारतीय रिज़र्व बैंक अपने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत बैंकिंग संपर्कियों (BCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचने की दिशा में प्रयासरत है।

सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों को मिला नीतिगत बढ़ावा

सुप्रबन्धित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी बैंकों (UCBs) की संवृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत वाले बैंकों को बहु-राज्यीय हैसियत देने पर लगे प्रतिबंधों को वापस लेने का प्रस्ताव किया है। अन्य राज्यों के कमजोर बैंकों का अभिग्रहण करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को उनके परिचालन क्षेत्र को लक्ष्य बैंक के पंजीकरण वाले संपूर्ण राज्य तक विस्तारित करने की अनुमति होगी।

वर्ष 2009-10 में मंदी ने शहरी सहकारी बैंकों का मार्जिन घटाया

वैश्विक वित्तीय खलबली के कारण आर्थिक मंदी की मार का सामना करते हुए भारतीय शहरी सहकारी बैंकों ने वर्ष 2009-10 में निवल ब्याजगत मार्जिन (NIM) में गिरावट रिपोर्ट किया है। वर्ष 2009-10 में क्षेत्र का निवल ब्याजगत मार्जिन वर्ष 2008-09 के 2.9% की तुलना में घट कर 2.5% हो गया। पिछले दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ में भी गिरावट आई है।

सूक्ष्मवित्त

पीड़ित सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने 1, 000 करोड़ रुपये की मांग की

नकदी से वंचित सूक्ष्म वित्त फर्मो ने बैंकों से 1, 000 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि की मांग की है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार की उद्योग को विनियमित करने की मुहिम के कारण पैदा हुए गंभीर चलनिधि संकट से पार पाने के घिरे हुए उद्योग के विकल्प तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। इन निधियों का उपयोग किसी भी सूक्ष्म वित्त संस्था के चलनिधि संकट से निपटने, चूक को रोकने तथा उसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश के बाहर अल्प (token) संवितरण की अनुमति देने के लिए किया जाएगा, ताकि वहां वसूलियों का क्रम जारी रहे।

बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देना पुन: शुरू करने पर सहमत, किन्तु सतर्कता बरतने की सलाह के साथ

बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार पुन: आरंभ करने पर सहमत हो गए हैं, किन्तु उनसे फिसलन को रोकने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा है। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उनकी निधियों का 75-80% अंश बैंक उधारियों के माध्यम से, 15% इक्विटी से और 10% नकदी प्रतिभूतियों जैसे अन्य स्रोतों से जुटाती हैं। बैंक विशेषत: उन सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को, जिनका आन्ध्र प्रदेश में भारी मात्रा में ऋण जोखिम (एक्सपोजर) था और जो प्राप्य राशियों की साप्ताहिक वसूली किया करते थे, उधार देने के प्रति अनिच्छुक हो गए थे।

अब प्रतिभूत सूक्ष्म वित्त ऋणों की कोई मांग नहीं

निवेशक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के प्रतिभूत ऋणों से कतरा रहे हैं, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के कारण वसूलियां धीमी हो गई हैं, जिससे अन्तर्निहित पोर्टफोलियो के प्रति अनिश्चितता व्याप्त हो गई है। देश के सूक्ष्म वित्त का एक तिहाई उधार आन्ध्र प्रदेश में दिया जाता है। प्रतिभूतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अपने ग्राहकों को दिए गए ऋणों से प्राप्य राशियां समूहित करती हैं और इन्हें बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा पारस्परिक निधियों जैसे अन्य पक्षों को बेच देती हैं। पारंपरिक ऋण संविभाग की बिक्री अथवा समनुदेशन के विपरीत इस प्रक्रिया में सूक्ष्म वित्त संस्था के पोर्टफोलियो का श्रेणी निर्धारण किया जाता है और उसे ऐसी मानकीकृत प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जाता है, जिसका अधिक सरलतापूर्वक क्रय-विक्रय किया जा सकता है।

बीमा

नये व्यवसाय में जीवन बीमाकर्ताओं के प्रीमियम में 23% की वृद्धि

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यथा-प्रेक्षित जीवन बीमा उद्योग का कुल प्रीमियम सितम्बर 2010 के अंत में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 23% की वृद्धि के साथ 1, 25, 254 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि नये व्यवसाय प्रीमियम में हुई ऋण वृद्धि के कारण तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दर्शाए गए सुदृढ़ कार्य-निष्पादन के भी कारण हुई है। यह वृद्धि इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उक्त अवधि में यूनिट-सम्बद्ध बीमा योजनाओं (ULIPs) की उत्पाद प्रोफाइल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

सरल मानदंड बैंकों को सहायक बीमा कम्पनियों में अतिरिक्त पूंजी लागाने में सहायक होंगे

बैंकों की उनकी सहायक बीमा कम्पनियों में अतिरिक्त पूंजी लगाने में सहायता करने की एक मुहिम में सहायक कम्पनियों (बीमा कम्पनियों सहित) की प्रदत्त इक्विटी में सम्पूर्ण निवेश को टियर I और टियर II पूंजी प्रत्येक में से 50% की दर से घटा दिया जाएगा। इस प्रकार, बैंक सहायक बीमा कम्पनियों में अधिक पूंजी निषेचन करने में समर्थ होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसके नये मानदंडों को लागू करने हेतु सहायक कम्पनियों में निवेश की प्रारंभिक सीमा को भी 30% से घटा कर 20% कर दिया है।

पूंजी बाज़ार

विदेशी संस्थागत निवेशकों का आस्ति आधार बढ़ कर 11 लाख करोड़ से अधिक

भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों के अन्तर्वाहों में अधिक बढ़ोत्तरी निश्चित होने के बावजूद सितम्बर, 2010 के प्रबन्धन बकाये के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों की आस्तियों से सम्बन्धित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के आंकड़े 11,24,352 करोड़ रुपये के रूप में अब तक की सर्वोच्च वृद्धि दर्शाते हैं। जेपी कैपिटल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनुसंधान श्री अब्बास मर्चेंट का कहना है कि "निवेशकों के लिए उभरते बाज़ारों, विशेषत: भारत और जिंसों को छोड़कर जाने के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं उपलब्ध हैं।"

बंबई शेयर बाज़ार, राष्ट्रीय शेयर बाज़ार ने शेयरों को निगरानी के तहत रखने हेतु मानदंड जारी किए

बंबई शेयर बाज़ार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार (NSE) ने शेयरों को निगरानी के तहत रखने हेतु नियम प्रकाशित किए हैं। यह कार्रवाई किसी शेयर के व्यापार से व्यापार तक (T-T) समूह में समावेशन या बहिर्वेशन के पूर्व कीमतों में होने वाले तीव्र उतार-चढ़ाव के अनुसरण में की गई है।

जिंस (पण्य) बाज़ार

एनसीडी शेयर बाज़ार ने कृषि सूचकांक की शुरूआत की

राष्ट्रीय जिंस एवं व्युत्पन्नी शेयर बाज़ार (NCDEX) ने भारत में शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली कृषि-जिंसों के लिए एक विश्वसनीय आधार उपलब्ध कराने हेतु 'धान्य' नामक कृषि सूचकांक की शुरूआत की है। भविष्य में समृद्धि के रूप में जाना जाने वाला धान्य शेयर बाज़ार के मंच पर 10

सर्वाधिक अनिरुद्ध कृषि जिंसों का निरूपण करता है। प्रत्येक जिंस का आधा भार देश के कुल उत्पादन को प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य आधा भार शेयर बाज़ार के घटक पर चलनिधि कारक का निरूपण करता है। प्रत्येक जिंस से सम्बन्धित भार शेयर बाज़ार के मंच पर हुए क्रय-विक्रय के परिमाण और राष्ट्रीय आर्थिक महत्व के आधार पर भिन्न-भिन्न होगा।

अन्तरराष्ट्रीय समाचार

संघर्षरत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फेडरल रिज़र्व 600 बिलियन डालर के खज़ाने खरीदेगा

अमरीकी फेडरल रिज़र्व बेरोज़गारी घटाने और अवस्फीति रोकने के लिए रिकार्ड प्रोत्साहन को विस्तारित करते हुए तथा अपनी विश्वसनीयता को जोखिम में डालते हुए 600 बिलियन डालर के अतिरिक्त खज़ाने की खरीद करेगा। नीति-निर्माताओं, जिन्होंने प्रति माह लगभग 75 बिलियन डालर की नई खरीदियों का लक्ष्य निर्धारित किया है, उक्त कार्यक्रम को अधिकतम रोज़गार उपलब्ध कराने और मूल्य स्थिरता के उद्देश्य से सर्वोत्तम विधि से समायोजित करेंगे। केन्द्रीय बैंक ने एक विस्तारित अवधि तक ब्याज दरों को कम रखने का अपना वचन निभाया है।

स्वर्ण मानक नहीं, किन्तु उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक के अध्यक्ष

विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री रॉबर्ट जोयेलिक का कहना है कि वे विनिमय दरों के रूप में स्वर्ण मानक की वापसी की वकालत नहीं करते, किन्तु उन्होंने उक्त धातु को "कमरे में मौजूद ऐसे हाथी" के रूप में वर्णित किया था, जिसे नीति-निर्माताओं द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। श्री जोयलिक, जो विश्व बैंक और सिंगापुर सरकार द्वारा आयोजित आधारभूत सुविधा सम्मेलन में भाग ले रहे थे, ने कहा कि राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे विनिमय दरों के परे देखें और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करें।

आयरलैण्ड संभाव्य सहायता की पूर्वपीठिका के रूप में बैंक सम्बन्धी वार्तालाप आरंभ करेगा

यूरोपीय संघ और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेषज्ञों ने यूरोप के बढ़ते वित्तीय संकट को टालने के लिए संभाव्य सहायता पैकेज की पूर्वपीठिका के रूप में आयरलैण्ड के कर्ज से लदे बैंकों की बहियों की छानबीन का कार्य आरंभ कर दिया है। 16 देशीय यूरो क्षेत्र के वित्तीय प्रमुखों का कहना है कि संयुक्त मूल्यांकन इस बात का निर्धारण करेगा कि आयरलैंड बैंकिंग प्रणाली की मरम्मत स्वयं

अपने स्तर पर करेगा अथवा 750 बिलियन (1 ट्रिलियन डालर) यूरोपीय संघ-अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उद्धार निधि का सहारा लेगा।

लाभांश बहाल करने से पूर्व फेडरल रिज़र्व को बैंकों की जांच की दरकार

फेडरल रिजर्व के अनुसार बड़े बैंकों को दबाव परीक्षणों के एक नये दौर से - इस बार इस बात का निर्धारण करने के लिए कि वे अपने शेयरों के लाभांश जुटाने की शुरूआत करने की दृष्टि से वित्तीय रूप से पर्याप्त सुदृढ़ हैं या नहीं, गुजरने की आवश्यकता होगी। उक्त घोषणा बैंकों द्वारा विनियामक पर वित्तीय कम्पनियों को लाभांश बहाल करने की अनुमति दिए जाने हेतु कई महीनों तक दबाव डाले जाने के बाद की गई। वित्तीय प्रणाली के फेडरल रिज़र्व द्वारा बचाव की कार्रवाई किए जाने के बाद लाभाशों में कटौती की गई थी।

चीन ने बैंकों की आरक्षित निधि के अनुपात में वृद्धि की

चीन ने इस वर्ष में पांचवीं बार बैंकों को आदेश दिया है कि वे विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ती मुख्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और आस्ति-बुलबले (asset-bubble) के जोखिमों को सीमित रखने के लिए वित्तीय प्रणाली से नकदी निष्कासित करते हुए अपेक्षाकृत भारी आरक्षित निधियां अलग रखें। चलनिधि प्रबन्धन को तीव्र किए जाने तथा साख एवं ऋण को लगभग नियंत्रित करने के लिए 29 नवम्बर से उक्त अनुपात में 25 आधार अंकों की वृद्धि हो गई है।

कर्ज संकट से यूरो को कोई जोखिम नहीं

यूरोपीय प्रतिमोचन (bailout) निधि के प्रधान श्री क्लास रेगलिंग का कहना है कि कर्ज संकट के परिणामस्वरूप पुर्तगाल, ग्रीस और आयरलैण्ड द्वारा प्रतिमोचन की मांग किए जाने के बावजूद 16 राष्ट्रों वाली यूरो मुद्रा के विफल हाने की कोई संभावना नहीं है।

अर्थव्यवस्था

अमेरिका में आर्थिक पुनरुत्थान के संकेत

वैयक्तिक उपभोग व्यय में मामूली वृद्धि तथा निजी मालसूचियों में आए परिवर्तन की पृष्ठभूमि में इस वर्ष की तीसरी तिमाही में अमेरिका का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दूसरी तिमाही के 1.7% की तुलना में 2% बढ़ा। उक्त आंकड़ों से विश्व की सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें दशकों

की भीषण आर्थिक मंदी के बाद पुनरुत्थान हो रहा है, में दोहरी गिरावट वाली मंदी के भय को विराम लग सकता है।

आधार दर और विदेशी संस्थागत अन्तर्वाहों के सौजन्य से ऋण बाज़ार में सक्रियता परिलक्षित

भारतीय ऋण बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मुद्रा प्रवाह बढ़ा दिए जाने तथा कम्पनियों के विदेशी उधारों और वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से अधिक निधियां जुटाए जाने की ताक में होने के फलस्वरूप कारपोरेट ऋण बाज़ार में ऐसी तेजी परिलक्षित हो रही है, जो इसके पूर्व कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। बैंक ऋणों के लिए नयी आधार-दर प्रणाली और ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशक सीमा बढ़ाने के सरकारी निर्णय ने खेल को सुस्पष्ट रूप से परिवर्तित कर दिया है। कारपोरेट बॉण्डों की पुनर्खरीद की अनुमति देने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के नये दिशानिर्देश बाज़ार को और अधिक व्यापकता प्रदान कर सकते हैं। भारतीय ऋण बाज़ार में केवल इसी कैलेण्डर वर्ष में 10 बिलियन डालर के लगभग रकम प्रवाहित हो चुकी है।

बुलबुलों को रोकने के लिए एशिया को पूंजी नियंत्रण की आवश्यकता पड़ सकती है

एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी नियंत्रण अपनाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका द्वारा मात्रात्मक सहूलियत दिए जाने से क्षेत्र के स्टॉक, मुद्रा और सम्पत्ति बाज़ार में, विश्व बैंक द्वारा यथा-वर्णित रूप में आस्ति-बुलबुले पैदा होने के खतरा हो सकता है। "किसी भी नियंत्रण को अस्थायी तौर पर लक्ष्यित तथा विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने हेतु निर्मित होना चाहिए" ये विचार हैं विश्व बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री मुलयानी इन्द्रावती के। "इसमें अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा (hot money) को एक वर्ष तक की लम्बी अवधि तक रोक रखने वाले देशों का समावेश हो सकता है।" फेडरल रिज़र्व ने अमरीकी आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के उद्देश्य से तथाकथित मात्रात्मक सहूलियत (QE2) के अपने दूसरे प्रयास में 600 बिलियन डालर के दीर्घकालिक सरकारी बॉण्डों को खरीदने की योजना की घोषणा की है। एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के नीति-निर्माताओं ने चेतावनी दी है कि इससे डालर को दबाने तथा पूंजी का उभरते बाज़ारों को पलायन जैसा पार्श्ववर्ती प्रभाव हो सकता है।

भारत 9% की संवृद्धि की दिशा में लौटने के लिए तत्पर

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विनिर्माण क्षेत्र में हाल के मंदी के संकेतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था 9% की वृद्धि के पथ पर वापस आने हेतु तत्पर है। श्री मुखर्जी का कहना है कि "इस समय उपस्थित चुनौती है 9% से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद के

उच्च वृद्धि पथ पर शीघ्रतापूर्वक वापस आना तथा एक या दो वर्ष में 'दो अंकों वाली वृद्धि के अवरोध' को पार करने के साधनों की तलाश करना। हमारा उद्देश्य है विकास प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस संवृद्धि को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए इस वृद्धि को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहना। समानांतर रूप से, हम अभिशासन के विभिन्न स्तरों पर अपनी प्रणालियों, ढांचों और संस्थाओं में विद्यमान कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान दे रहे हैं।"

नयी नियुक्तियां

श्री एम. नरेन्द्र ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

श्री एन. शेषाद्रि ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे केनरा बैंक में महा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

श्री अमिताभ गुहा ने गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में साउथ इंडियन बैंक (SIB) में सेवारंभ कर दी है। वे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के भी भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक हैं।

श्री अनिल रामचन्द्रन ने क्रेडिट कार्ड कारबार के प्रधान के रूप में इंडसइंड बैंक में सेवारंभ कर दी है।

श्री विक्रम टंडन ने एचएसबीसी में मानव संसाधन के प्रधान के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

सेन्ट्रल बैंक ने एएमडब्ल्यू के साथ समझौता किया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एशिया मोटर वर्क्स ने एक ऐसा समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया है, जिसमें बैंक एएमडब्ल्यू के वाहन ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

साउथ इंडियन बैंक ने डेबिट कार्ड आरंभ करने हेतु वीसा के साथ गंठजोड़ किया

विश्व के सबसे बड़े खुदरा भुगतान नेटवर्कों में से एक वीसा के साथ रणनीतिक गंठजोड़ करते हुए, केरल स्थित साउथ इंडियन बैंक ने एसआईबी वीसा इंटरनेशनल डेबिट- व- शॉपिंग कार्ड की शुरूआत की है।

वीई कॉमर्शियल ने पंजाब नैशनल बैंक के साथ समझौता किया

वीई कॉमर्शियल वेहिकल ने ग्राहकों को उसके वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु पंजाब नैशनल बैंक (PNB) के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया है।

यूनियन बैंक का नोकिया और ओबोपे के साथ समझौता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नोकिया और ओबोपे के साथ मिल कर पूरे देश में चल (मोबाइल) वित्तीय सेवाओं की शुरूआत करने हेतु भागीदारी की घोषणा की है। यूनियन बैंक मनी कही जाने वाली यह भागीदारी शीघ्र ही देश भर के उपभोक्ताओं को चल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

येस बैंक ने शिन्सेल बैंक के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया

येस बैंक और शिन्सेल बैंक ऑफ जापान ने कम्पनियों को दो राष्ट्रों के बीच होने वाले सीमा-पार सौदों के सम्बन्ध में सलाह देने हेतु एक समझौता हस्ताक्षरित किया है। उक्त गंठजोड़ भारत-जापानी गलियारे (corridor) में निवेश प्रवाह को और अधिक आवर्धित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

इंडियन बैंक, वीजमान फॉरेक्स गंठजोड़

इंडियन बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में काउंटर पर विदेशी विप्रेषण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वीजमान फॉरेक्स लिमिटेड के साथ एक करार हस्ताक्षरित किया है। यह करार वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के माध्यम से मुद्रा अंतरण सेवाओं के संचालन के लिए है। उक्त करार के तहत व्यक्तियों द्वारा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के माध्यम से 204 से अधिक देशों से किए जाने वाले वैयक्तिक विप्रेषणों का लाभार्थियों को इंडियन बैंक की शाखाओं में तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा।

संस्थान समाचार

सर पीएमटी व्याख्यान 9 दिसम्बर 2010 को आयोजित

27वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान 9 दिसम्बर, 2010 को भारतीय अनुपम पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकनी द्वारा "वित्तीय समावेशन का ध्येय - क्या हम अत्युत्कृष्ट बिन्दु पर पहुंच गए हैं ?" विषय पर भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, मुंबई में दिया गया। उक्त व्याख्यान संस्थान की वेब साइट www.iibf.org.in. पर उपलब्ध है।

मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक

संस्थान ने 3 दिसम्बर को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की हाल की पहलकदमियों पर चर्चा करने हेतु महा प्रबन्धकों (GMs) / मानव संसाधन प्रमुखों की एक बैठक का आयोजन किया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रस्तुतीकरण

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 26/11/2010 को भारतीय बैंक संघ की प्रबन्ध समिति के समक्ष इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की हाल की उन गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण किया, जिनमें सीएआईआईबी (2010) और निरंतर स्वरूप वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों पर अधिक संकेन्द्रण था।

स्थूल शोध प्रस्ताव

8 शोधार्थियों ने क्षेत्रीय लेखा-परीक्षा कक्ष (RAC) के सदस्यों के समक्ष उनके शोध प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया और 4 शोधार्थियों को वर्ष 2010 की स्थूल शोध प्रोजेक्ट प्रदान किया गया है (विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें) ।

महत्वपूर्ण सूचना

संस्थान के सभी आजीवन सदस्यों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे संस्थान से सभी प्रकार के पत्राचार / सामग्री समय से प्राप्त करने के लिए कृपया उनके पते में हुए परिवर्तन की सूचना संस्थान के कार्पोरेट / आंचलिक कार्यालय को ई-मेल द्वारा वेब साइट पर दिए गए आरूप में दें।

कार्पोरेट कार्यालय	mem-services@iibf.org.in.
पश्चिमी अंचल	iibwz@ www.iibf.org.in.
पूर्वी अंचल	iibez@ www.iibf.org.in.
उत्तरी अंचल	iibnz@ www.iibf.org.in.
दक्षिणी अंचल	iibsz@ www.iibf.org.in.

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

बीआईएस क्या है ?

हां। मैं समझाता हूं।

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक अनुसंधान, सांख्यिकी निर्माण, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन तथा केन्द्रीय बैंकों के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे कई एक कार्यकलापों का संचालन करता है। यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक केन्द्रीय बैंकरों के बीच सुज्ञात है, तथापि वह वाणिज्यिक बैंकों के बीच अब भी दुर्बोध बना हुआ है। यह वाणिज्यिक बैंकरों के जीवन को केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से प्रभावित करता है। जोखिम प्रबन्धन और अन्य स्थूल विवेकसम्मत प्रबन्धन से सम्बन्धित केन्द्रीय बैंकों के कई एक निर्देश / दिशानिर्देश अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की सलाहों की उपशाखाएं होते हैं। अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा संचालित विविध आवधिक अध्ययनों / सर्वेक्षणों में कई एक वाणिज्यिक बैंक भी सहभागिता करते हैं। इस प्रकार विश्व की इस सर्वाधिक पुरानी संस्था के बारे में जानना रोचक है। हम अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक की भूमिका और प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए अलेखों की एक श्रृंखला की योजना बना रहे हैं, जो हमें विश्वास है कि बैंकिंग के गंभीर विद्यार्थियों और व्यवसायियों एवं वित्तीय व्यावसायिकों के लिए रोचक सिद्ध होंगे।

यहां, हमारा अभिप्राय विजन के आगामी अंक से अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक को रहस्योद्‌घाटित करना है। हम अपनी नयी पहल के सम्बन्ध में आपकी प्रति-सूचना आमंत्रित करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बचाव लेनदेन

एक प्रकार का ऐसा लेनदेन जो विकल्प एवं वायदा संविदाओं जैसी व्युत्पन्नियों के उपयोग के साथ निवेश जोखिम को सीमित कर देता है। बचाव लेनदेन में किसी क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में एक निश्चित मात्रा में अभिलाभ अथवा हानि सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार में विदेशी मुद्रा की क्रय-विक्रय की प्रतिकूल स्थिति को खरीदा जाता है। उनका उपयोग पोर्टफोलियो प्रबन्धकों द्वारा पोर्टफोलियो जोखिम और अस्थिरता अथवा अवरुद्ध लाभ कम करने हेतु किया जाता है। बचाव लेनदेन साधारण अभिलाभ और हानि कर विवेचन के अध्ययीन होते हैं। हालांकि, सीमित भागीदारों की बचाव हानियां सामान्यतया उस वर्ष के लिए उनकी कर-योग्य आय तक सीमित होती हैं। बचाव निधियां इस प्रकार के लेनदेन का व्यापक रूप से उपयोग करती हैं।

शब्दावली

चलनिधि समायोजन सुविधा

मौद्रिक नीति में प्रयुक्त एक ऐसा साधन जो बैंकों को पुनर्खरीद करारों के माध्यम से मुद्रा उधार लेने में समर्थ बनाता है। यह व्यवस्था बैंकों को चलनिधि दबावों का प्रत्युत्तर देने में समर्थ बनाती है और इसका उपयोग सरकारों द्वारा वित्तीय बाज़ारों में वित्तीय स्थिरता के प्रति आश्वस्त करने में किया जाता है। चलनिधि समायोजन सुविधाओं का उपयोग बैंकों की आर्थिक अस्थिरता की अवधियों के दौरान अल्पावधिक नकदी की किसी कमी या उनके नियंत्रण के परे शक्तियों द्वारा पैदा किए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के दबाव से निपटने में सहायता करने के लिए किया जाता है। विविध बैंक पूनर्खरीद करार के माध्यम से पात्र प्रतिभूतियों का उपयोग संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में करेंगे तथा निधियों का उपयोग अपनी अल्पावधिक आवश्यकताओं को कम करने में करेंगे, इस प्रकार स्थिर बने रहंगे।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 / दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

21500
21000

20500
20000
19500
19000
18500
18000

01/11/10 04/11/10 11/11/10 12/11/10 18/11/10 19/11/10 22/11/10 23/11/10
24/11/10 25/11/10 26/11/10 29/11/10 30/11/10

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

78
73
68
63
58
53
48
43

01/11/10 03/11/10 08/11/10 09/11/10 11/11/10 12/11/10 15/11/10 16/11/10
18//11/10 19/11/10 23/11/10 26/11/10 29/11/10 30/11/10

अमरीकी डालर यूरो जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

-डालर के समक्ष रुपये में क्रमिक मूल्यह्रास परिलक्षित।
-आयातकों द्वारा वर्धित खरीदियों पर रुपया लुढ़का।
-यूरो अनियमित बना रहा और रुपये के समक्ष मूल्यह्रासित हुआ।
-स्टर्लिंग श्रेणीबद्ध रहा।

भारित औसत मांग दरें

7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00

01/11/10 03/11/10 04/11/10 06/11/10 09/11/10 11/11/10 13/11/10 16/11/10 19/11/10 23/11/10 24/11/10 25/11/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, नवम्बर, 2010

मांग मुद्रा बाज़ार में अस्थिरता परिलक्षित हुई।

मांग दरें 6.5 और 7.3 के बीच मंडराती रहीं।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,

मुंबई - 400 005

टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न दिसम्बर, 2010